

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री डी०जे०बी०दायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री आदित्य कुमार रस्तेगी	सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग।	सदस्य
(3)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(4)	श्री एस०डी०वर्मा	उप सचिव, वित्त	सदस्य
(5)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(6)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(7)	श्री भीरू मजहरा जलो	सदस्य, विधान सभा	सदस्य
(8)	श्री माला प्रसाद	सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(9)	श्री वरान सिंह		सदस्य
(10)	श्री आर०एस०मायुर	अवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र.सं.	विषय	संख्या संख्या	निर्णय
1		3	4

1- दिनांक 30-3-82 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

111/(1)/82

परिषद की दिनांक 30-3-1982 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी:-

- 1- मद सं०-2 परिषद की बैठक दिनांक 18-2-1982 की अनुपालन आस्था की उप मद सं०-20 में परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आगे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-
 " यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक व्यय वार्षिक व्यय के आधार पर निकासा जाना चाहिये। प्रशासनिक व्यय को वास्तविक धिति स्पष्ट करने हेतु निर्माण कार्य भूमि विकास कार्य तथा भूमि अध्यापन कार्य के सम्बन्ध में हुये प्रशासनिक व्यय को ध्यान में रखकर प्रतिशत निकासा जाय।"
- 2- उसी तरह मद संख्या-2 की उप मद सं०-29 के तीसरे प्रस्ता में शब्दों को निकास कर निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त पूर्व और इसके स्थान पर शब्दों "हत होलने से पूर्व" लिख दिया जाय।

कु०प०र०

Handwritten signature

2-परिषद की बैठक
दिनांक 30-3-1982
की अनुपालन आधा।

111/(2)/82

परिषद द्वारा दिनांक 30-3-1982 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आधा की समीक्षा की गई और निम्न-लिखित निर्णय लिये गये:-

1-वाहनों के ब्रय करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का पूर्ण प्रयास किया जाय ताकि क्षेत्रीय अधिकारियों के लिये वाहनों को ब्रय कर शीघ्र उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

इस संदर्भ में सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग ने समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

2-सहायक निदेशक(प्रचार) का पद जो बहुत अरसे से रिक्त है भराने की कार्यवाही अविलम्ब पूरी करने का निर्णय लिया गया।

3-भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित मामले तथा इससे जुड़ी हुई अन्य समस्याओं के बारे में शासन स्तर पर जो बैठक प्रस्तावित है उसे शीघ्र कराने तथा शासन स्तर पर लम्बित सभी इस प्रकार के मामलों का समुचित निस्तारण कराने का निर्णय लिया गया।

परिषद को राजस्व परिषद के सदस्य के समक्ष हुई बैठक तथा इसमें किये गये विचार विमर्श तथा लिये गये निर्णयों से अवगत कराया गया। परिषद में निर्णय लिया गया कि कानपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के रिक्त पद पर शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा शीघ्र ही तेनाती करायी जाय तथा आपस की वाचस्पति द्वारा भूमि अर्जित कराने के लिये यथेष्ट कार्यवाही करने के पूर्व राजस्व विभाग द्वारा उपयुक्त शासनादेश की निर्गम होना चाहिये।

4-मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवासगृहों पर किये गये गैर-आननी तथा अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में सचिव, आवास ने बताया कि माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर एक बैठक यथाशीघ्र आयोजित करायी जा रही है। यह निर्णय लिया गया कि उक्त बैठक शीघ्र कराकर पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवासगृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को अविलम्ब हटाया जाय तथा जो भी परिषद को पहुंची है की पूर्ण तौर से प्रतिपूर्ति परिषद के पक्ष में की जानी चाहिये।

5-इन्दिरा नगर लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग सम0ए0-75 के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव स्तर से अविलम्ब निर्णय कराया जाय। सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग ने यह आश्वासन दिया कि वह सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क करके इस मामले का शीघ्र निस्तारण करायेंगे।

6-परिषद की सभी निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के संबंध में सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग ने परिषद को अवगत कराया कि उनके स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र भेज दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में परिषद ने निर्णय लिया कि शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों की प्रतियां प्राप्त कर व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करके समस्त कालोनीज़

D. Paul

कृ०प०उ०

शासन के नगर विकास विभाग के सचिव से संपर्क करके प्रस्ताव परिषद के सम्मुख रखा जाय कि आवासीय योजना कार्यान्वित हो जाने के बाद योजना का हस्तान्तरण तथा रख-रखाव किस नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

- 15- गोपेश्वर जिला चमौली में स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराकर उपयुक्त प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- 16- निर्माण कार्य हेतु पूर्ण मात्रा में सीमेंट आवंटित कानिका फिर से प्रयास किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित क्रेटा की सीमेंट समय से उठ ली जाती है और कोई क्रेटा लेप्स नहीं हो जाता है। अनुपालन आख्या देते समय पूर्ण विकल्प परिषद के सम्मुख रख दिया जाय।
- 17- शहरजहाँपुर, हरिकद्वार, बाशीपुर तथा बौली नगरों में परिषद की ओर योजनायें चलाने के लिये भूमि का चयन परिषद द्वारा निर्धारित सीमा अधि(जन-1982) के अन्तर्गत अवश्य करा लिया जाय और निश्चित नगर-वार प्रस्तावों को परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
- 18- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संकथ में अन्य प्रदेशों के आवास एवं विकास परिषदों के प्रशासनिक व्यय की स्थिति मँग ली जाय और बसका प्रोग्राम का, आख्या दी जाय। साथ ही साथ यह समाय रहे कि प्रशासनिक व्यय वार्षिक व्यय के आधार पर निकाला जाना चाहिये। प्रशासनिक व्यय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्माण कार्य, भूमि विकास कार्य तथा भूमि अध्याप्ति कार्य के सम्बन्ध में हये प्रशासनिक व्यय को अध्यान में रखकर प्रतिशत निकाला जाय। तदनुसार समयक आख्या परिषद के सम्मुख अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
- 19- परिषद की भवन निर्माण विनियमावली के संकथ में गठित उप समिति की बैठक शीघ्र कराकर उप समिति की आख्या तथा सुस्तियाँ परिषद की अगली बैठक में रख दी जाय।
- 20- बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 के लिये अनुपयुक्त तथा आयोज्य भूमि का चयन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के संदर्भ में जाँच आख्या प्राप्त कर परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखा जाय।
- 21- शामली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, शामली के लिये अनुपयुक्त तथा आयोज्य स्थल चयन के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में जाँच आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किये जायें।
- 22- मैनीताल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के संदर्भ में शासन के छवतीय विकास विभाग व आयुक्त, कुमाय मण्डल, मैनीताल को अनुस्मारक पत्र भेजकर उनको सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

परिषद

Handwritten signature

23- मोदीनगर में हापुड़ रोड पर भूमि अधिग्रहण की संभावना के बारे में प्रस्ताव तथा शीघ्र परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

24- निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिये जिस विस्तृत प्रोपर्टी को अपनाने का निर्णय 30-3-1982 की परिषद की बैठक में लिया गया था उस प्रोपर्टी पर विस्तृत तथा पूर्ण विवरण सहित आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

25- लखनऊ नगर के किसी दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्ग योजना में 25 भवनों का आवंटन हत निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही किया जाय ताकि जाँचियों को निर्माण कार्य के दौरान ही रहे निर्माण की गुणवत्ता देखने को मिल सके। इस प्रकार यदि इस नये पद्धति के अनुसार भवनों की गुणवत्ता में सुधार होना/परिष्कृत हो जाता है तो उसे परिषद की भावी योजनाओं में लागू करने पर विचार किया जायेगा।

परिष्कृत

26- दुर्बल आय वर्ग के भवनों में सीमेंट की छत के शान पर जैक आर्च की छत डालने के बारे में निर्णय परिषद की पूर्व बैठक में लिया जा चुका है कि लखनऊ की किसी योजना में इसका प्रयोग अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाय। इस निर्णय को तत्परता से कार्यान्वित किया जाय।

27- गोरखपुर में 'सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम' के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में रख दिया जाय।

28- प्राग नारायण रोड योजना, लखनऊ की भूमि के विषय में विस्तृत जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जाय और यदि उक्त योजना में समाविष्ट भूमि सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नजूल सम्पत्ति है तो नजूल सम्पत्ति की पूर्ण विवरण सूचना का शासन को एक निश्चित प्रस्ताव उक्त भूमि के हस्तान्तरण हेतु भेज दिया जाय।

30- लखनऊ नगर में माननीय विधायकों के लिये 'सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम' के अन्तर्गत आवास योजना के निर्माण के संदर्भ में शासनादेश शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

31- सतानपुर में आवासीय योजना चलाने के लिये योजना विभाग से संपर्क करके स्थल का चयन शीघ्र ही किया जाय और निर्माण कार्य तत्परता से प्रारम्भ कराया जाय।

32- गोरखपुर में समाविष्ट 'स्थानिक डायसिस' की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तावित

33- लखनऊ नगर में आवासीय योजना चलाने के लिये 'सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम' के अन्तर्गत आवास योजना के निर्माण के संदर्भ में शासनादेश शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

बर्ता शीघ्र सम्पन्न कराके वस्तुस्थिति से परिषद को अवगत कराया जाय।

- 33- देवपुरा पारा भूमि विकास सर्व गृहस्थान योजना लखनऊ के सम्बन्ध में विचार तथा निर्णय लेने के पूर्व और राजाजीपुराम् कालोनी को जन्म साधारण में अधिक्त लोकप्रिय बनाने के सिलसिले में राजाजीपुराम् स्पीच रोड योजना बनाई जानी चाहिए इस योजना को तैयार कर परिषद की अगली बैठक में रखवाने को व्यवस्था कीजाय।
- 34- परिषद को विभिन्न वर्षों का बजट और पक्का चिट्ठा (Balance sheet) विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखने के संदर्भ में अब तककी गई कार्यवाही को सूचना परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
- 35- वर्ष-1982-83 तथा आने वाले वर्षों के आय व्ययकी के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि परिषद की बैठकों में प्रत्येक बैठक में होने वाले आय-व्ययकी के आंकड़े और मोटे मद्दवार व्ययकी स्थिति रख दी जाय। परिषद की बैठक में रखने के पूर्व इसकी समीक्षा परिषद की अनुसूचना समिति किया करेगी।
- 36- सिविल लाइसेंस भूमि विकास सर्व गृहस्थान योजना, कानपुर की भूमि के संदर्भ में परिषद की बैठक दिनांक 30-3-1982 में लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र ही सम्पन्न करायी जाय।
- 37- श्री आर०सी०सकेना, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्राप्तसिविल इंजीनियरिंग की हिरी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न होने के सम्बन्ध में परिषद को इस मामले को पृष्ठभूमि तथा सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया गया। एक तथ्यात्मक टिप्पणी जिसमें परिषद के विधि अधिकारी का मत है परिषद के सम्बन्ध विचारार्थ प्रस्तुत हुई। परिषद ने इस मामले में गहने रख से विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विधि अधिकारी की राय को देखते हये और इस बात को भी देखते हये कि श्रीसकेना की सेवाओं का संवित्तिपरिषद में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया गया था अतएव परिषद के सम्बन्ध अन्य कोई विवेक नहीं है सिवाय कि इस प्रकार को सम्पन्न कर दिया जाय। परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि विधान सभा की सार्वजनिक उपद्रम समिति को परिषद के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाय।

3-बन्दि गानुगर योजना लखनऊ के सेक्टर-5 व 6 के बीच ग्रीन बेल्ट में प्रस्तावित सञ्जी मण्डल के यरिनल का निर्माण।

111/(3)/82

[Handwritten Signature]

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यरिनल के स्थान पर शीवालयों का निर्माण कराया जाय और अस्तु परिषद के सम्बन्ध संशोधित प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

50/030

यह भी निर्णय लिया गया कि सेक्टर-5 व 6 के बीच 'ग्रीन वर्ज' में फ्लैट प्रेमसा के निर्माण के पश्चात् ग्रीन वर्ज के क्षेत्र में जो कमी आये उसे योजना के अन्य क्षेत्र से पूरा कराया जाय तथा ग्रीन वर्ज का पूरा क्षेत्र अगली वर्षा की शुरु के दौरान पेड़ पौधों से आश्रित कर दिया जाय।

4-परिषद द्वारा प्रद्विष्ट सम्पत्ति के प्रदिष्टी की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति को उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में करने के संबंध में।

111/(4)/82

परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला जज का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का प्रावधान समाप्त करना उचित नहीं है। केवल इतना संशोधन विनियमों में कर दिया जाय कि जिला जज का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना उसी दशा में आवश्यक होगा जबकि सम्पत्ति का मूल्य ₹ 20, 000/= अथवा इससे अधिक होगा।

5- अविशेष रिक्त सम्पत्ति के प्रदेशन में उसी योजना के विस्थापित को करीयता।

111/(5)/82

परिषद ने विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अविशेष रिक्त सम्पत्तियों का प्रदेशन करते समय उसी योजना के विस्थापितों को वाप्यता देने हेतु प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में विधि अधिकारी की राय ले ली जाय और संशोधन का प्राप्त परिषद को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

6- राजाजीपुरम योजना, विधानसभा में श्री गुरु सिंह सभा को गारुडारी हेतु भूमि का प्रदेशन।

111/(6)/82

परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री गुरु सिंह सभा को उनके आवेदन-पत्र में लिये गये प्रयोजनों हेतु भूमि का प्रदेशन ~~अनुसूचित~~ परिषद को सौंपे जाये जो अनुसूचित है के अनुसार कर दिया जाय।

परिषद को संवेदन 111/6/82
- *Handwritten signature*

7- सुंदरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-3 इलाहाबाद (क्षेत्रफल 200 एकड़, अनुमानित लागत ₹ 320.740 लाख)

111/(7)/82

परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

8- बाँदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बाँदा (क्षेत्रफल-34 एकड़ अनुमानित लागत 38.43 लाख)

111/(8)/82

परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।

यह भी निर्णय लिया गया कि योजना में समाविष्ट असा नं०-972 जो नजल सम्पत्ति है और जिसे जिलाधिकारी ने अपने स्तर से हाल सिंचाई बण्ड, बाँदा को हस्तान्तरित कर दिया है को भी परिषद की योजना में सम्मिलित करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय।

9- बाराज पहासु रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना स०-2 बाराज, ~~क्षेत्रफल 89.90 एकड़ एवं अनुमानित लागत 174.75 लाख~~

111/(9)/82

परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।

Handwritten signature

1	2	3	4
10- शाहाबाद ग्राम विकास स्व. गृहस्थान योजना, शाहाबाद जिला-हरदोई (कैम्प-28 अनुमानित लागत ₹ 32.898 लाख)	111/(10)/82	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। परिषद द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा योजना की भूमि में से नयी लक्षित शाहाबाद के इवनी तथा प्रौद्योगिक हेतु 7.79। एकड़ भूमि की मांग की गई है जो में विचार-विमर्श आवास आयुक्त सहोदर जिलाधिकारी, हरदोई से करेंगे और अपने अंतिम विचार से परिषद को अगली बैठक में अवगत करायेंगे।	
11- सिविल लाइन्स ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2, बदायूं (कैम्प-121.73 एकड़ अनुमानित लागत ₹ 2.24 लाख)	111/(11)/82	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।	
12- नौबतपुर योजना, दारानगी में 380 मूल्य आयु वर्ग 1/81 डिजाइन के नए मकानों का निर्माण (अनुमानित लागत रुपये- 101.40 लाख)	111/(12)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।	
13- हड़को द्वारा वित्त पोषित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम - नौबतपुर बदायूं (स्कीम- नं०-1996-सी०-हड़को रूप की स्वीकृति रुपये 40.23 लाख)	111/(13)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।	
14- हड़को द्वारा वित्त पोषित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम रूपर स्कीम नं०-1998-सी० हड़को रूप स्वीकृति रुपये 25.12 लाख)	111/(14)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।	
15- चतुर्थ हड़को कम्पोजिट प्रोजेक्ट शाहपुर योजना सं०-1 गोरखपुर (स्कीम नं०-1999-सी०-हड़को रूप स्वीकृति रुपये 35.02 लाख)	111/(15)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।	
16- हड़को द्वारा वित्त पोषित प्रथम हड़को कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम हड़को (स्कीम नं०-1997- सी०-हड़को रूप स्वीकृति रुपये 34.69 लाख)	111/(16)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।	
17- 30प्र० आवास एवं विकास परिषद बुधबुधो तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 का विनियम-25 के अन्तर्गत पट्टों की अवधि समाप्त होने से पूर्व पट्टों का नवीनीकरण।	111/(17)/82	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि पट्टों की अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीनीकरण हेतु जो 'गाइड लाइन्स' बनायी गयी है उसके क्रम सं०-3 में उहाँ यह लिखा है कि किसी भी कारण कारण पर पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा वहाँ यह लिखा गया कि ऐसा होने पर पट्टों का नवीनीकरण	

(Handwritten Signature)

- सामान्यतः नहीं किया जायेगा।
 क्रम संख्या-4 केखान पर निम्न प्राविधान
 "गारह ताहन्स" में रख दिया जाय:-
 "पट्टे का मदीनीकाण परिषद द्वारा
 निर्धारित प्राकृत तथा निर्धारित शर्तों एवं
 प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा"।
- 18- प्रदेशान तथा पंजीकरण 111/(18)/82 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
 सखनी मामलों में उप
 आवास अधिकार को आवास बाधुक्त
 के अधिकारों का प्रतिनिधत्त।
- 19- गदरपुर भूमि विकास एवं 111/(19)/82 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
 गृहस्थान योजना गदरपुर
 जिला-नेनीताल (बि.नफ.न-
 23+30 एकड़ अनुमानित
 लागत 36.375 लाख)
- 20- बनरोहा भूमि विकास एवं 111/(20)/82 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
 गृहस्थान योजना स०न
 बनरोहा जिला सुपदाबाद
 (वि.नफ.न 10.89 एकड़
 अनुमानित लागत 14.66
 लाख)।
- 21- बनरोहा शहर में श्रीमती 111/(21)/82 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया कि प्रथमतः भूमि पर योजना चलाना उपयुक्त नहीं है।
 श्रीमती देवी शर्मा की भूमि
 को आवास योजना हेतु उप
 शर्तों के संकल्प में।
- 22- देहली रोड पर भूमि 111/(22)/82 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना के समाविष्ट श्री हरि कृष्ण गोयल की भूमि स०-588 अर्जन से अवमूल्यन का दी जाय लेकिन शर्त यह रहेगी कि इस भूखण्ड में निर्माण का हिस्सा कौटु कर जो शेष बची भूमि है का प्रयोग केवल बुसी भूमि के रूप में ही किया जायेगा।
 विकास एवं गृहस्थान
 योजना स०न, हरिद्वार
 में समाविष्ट श्री हरि
 कृष्ण गोयल की भूमि
 स०-588 को अर्जन से मुक्त
 करने के संकल्प में।
- 23- परिषद में इक्कीक्यूटिव 111/(23)/82 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
 टैनिंग की नियुक्ति के
 संकल्प में।
- 24- गदरौह मेरठ की योजना 111/(24)/82 परिषदद्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रेम पीयूष परिषद जो दो विशिष्ट भूखण्ड योजना के आवासीय क्षेत्र में है उसे ही से भूमि लेना चाहती है को प्रथमतः भूमि आवंटित करना संभव नहीं होगा। इसको सूचना प्रेम पीयूष परिषद को दे दी जायेगी।
 स०-7 में प्रेम पीयूष परिषद
 को धार्मिक स्थान खोलने हेतु
 भूमि का प्रदर्शन।

(Handwritten Signature)

1	2	3	4
25-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना, तबनऊ में श्रीमती कुश मथुरा की आपत्ति जो ब्रह्मप्लान पर दर्शाई गई सड़क के बीच में निर्मित भवन की ऊर्जन से मुक्त करने के विषय में है।	111/(25)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त दिग्गो में दिये गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। यह भी निर्णय लिया गया कि योजना में अन्य निर्माणों के साथ उपयोग हेतु आवश्यक भूमि छोड़ने हेतु जो मानक तैयार किये गये हैं उसे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को दिखाकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
26-	बुन्दावन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (क्षेत्रफल- 81.825 एकड़ अनुमानित लागत ₹ 70.223 लाख) के सम्बन्ध में नियोजन समिति को आख्या पर विचार।	111/(26)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। परिषद ने निर्णय लिया कि अधिनियम की धारा-31(1) के अन्तर्गत परिष्कार रहित स्वीकृति देती है और यह निर्णय भी लिया कि शासन का आदेश अधिनियम की धारा-31(2) के अधीन प्राप्त किया जाय।
27-	बायरास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं-1 (क्षेत्रफल 67 एकड़ अनुमानित लागत ₹ 157 लाख) के सम्बन्ध में नियोजन समिति को आख्या पर विचार।	111/(27)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। परिषद ने निर्णय लिया कि अधिनियम की धारा 31(1) के अन्तर्गत परिष्कार रहित स्वीकृति देती है और यह निर्णय भी लिया कि शासन का आदेश अधिनियम की धारा-31 (2) के अधीन प्राप्त किया जाय।
28-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं-1, गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राथमिकता (क्षेत्रफल लगभग 660.00 एकड़ तथा कुल अनुमानित लागत रुपये 18.50 करोड़)	111/(28)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं-3 गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राथमिकता (क्षेत्रफल लगभग 2127.00 एकड़ तथा कुल अनुमानित लागत रुपये 59.63 करोड़)	111/(29)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली राज्य की सीमा तक की अवशेष भूमि जो योजना की भूमि से निकट है को भी अधिग्रहण करने के लिये प्रस्ताव शीघ्रताशीघ्र तैयार कर परिषद के समक्ष लाया जाय।
30-	इन्दिरा नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित 192 फ्लैट्स इतरी के मृत्योवन में कमी की संशोधन किया जाना।	111/(30)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 30-6-1982 तक मृत्यु प्रति चञ्चलता ₹ 7000 रहेगा।
31-	कारपोरेट प्लान पर विचार	111/(31)/82	कारपोरेट प्लान पर विचार विमर्श किया गया। परिषद ने सर्वसम्मति से तैयार किये गये प्लान की सराहना की और यह निर्णय लिया कि कारपोरेट प्लान को ही आधार पर भविष्य में योजनायें चलाने हेतु समय समय पर परिषद के सम्मुख प्रस्ताव रखे जाने चाहिये। प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के लिये निम्न मांग दर्शन निदेश दिये गये:- 1- सभी जिला मुख्यालय जो अधि-सूक्ति है तथा अन्य ऐसे नगर जहाँ पंजीकृत मांग है, पंजीकृत लोगों की संख्या की वरीयताक्रम के अनुसार जैसे जैसे भूमि उपलब्ध होती जाय परिषद को योजनायें चलायी जाय।

Handwritten signature

कृ०प०उ०

